HARYANA VIDHAN SABHA

DEBATAES

19th July, 1968

Vol. I — No. 4

OFFICAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 19th July, 1968

	Page
Starred Questions	1
Observations by the Speaker	1
Call attention Notice	2
Presentation of the Budget for the Year 1968-69	2-15

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha debates Vol. I, No. 4,

Read	For	Page	Line
बढ़कर	बढ़कर	(4)3	7
बढ़ाने	बढ़ान	(4)3	12
ब्योरा	ब्योरा	(4)4	9
ब्योरेवार	ब्योवार	(4)7	19
Add between and		(4)10	2
शिक्षा	शिक्षा	(4)11	14
स्वास्थ्य	स्वास्थ्य	(4)11	34

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 19th July, 1968

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Chandigarh, at 9-30 A.M. of the Clock Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

Starred Question

Mr. Speaker : Hon. Members, I am afraid there are three question on the agenda for today. As information in regard to these questions could not be obtained by Governmnet in time, extension was sough and was granted.

(Hon. Speaker waited for some time if any hon. Member wanted to say anything about delay in collecting information by Government)

Observations by the Speaker

Mr. Speaker : Since nothing has baeen said from the Opposition Benches, I would like to make some observations myself. I would like to bring it to the notice of the Hon. Leader of the House that these questions os Shrimati Chandravati were received on the 3rd July, 1968, in my Secretariat and were sent to the Government on the 8th July, 1968. So reasonable time was allowed to the government to collect the necessary information.

I also want to bring it to the notice of the Government that I find that in regard to one question of Shri

Fateh Chand Vij, which was sent to the Government on 9th July, the Secretary concerned issued a circular letter asking ofther Departments for information, on the 17the July, 1968, where as the question was to answered on the floor of the House on the same day, i.e. on the 17th July, itself.

Shrimati Chandravati : Sir, may I know why this question No. 4 cannot be answered today? What is the hitch in that?

Mr. Speaker : As I have stated earlier, Government have to obtain information from different sources ; they asked for extension which was granted. But what I am really bringing to the notice of the House and particularly the Leader of the House, is that a certain question was sent to the Government on the 9th July, 1968. It was to be answered on the 17th July. The Secretary concerned, however, issued a circular letter on the 17the July, asking the Departments concerned to supply necessary information. So, what I want to impress is that the question hour is a very important means available to the hon. Members to seek information and to see that things are getting on well. I would, therefore, request that some special procdure be laid down whereby immediate action is taken by Government to supply information or to answer the question given notice of by the hon. Members as early as possible.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, आयंदा मै इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई इस तरह की देरी न हो लेकिन इसके साथ ही साथ मै आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि प्रश्न नं० पांच और छः इतने लम्बे है जिनका उत्तर तैयार करने के

लिये काफी समय की जरूरत थी। फिर भी भविष्य में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न का उत्तर निश्चित दिन पर ही दे दिया जाए।

Mr. Speaker : I am not really referring to the question No. 5 amd 6 because extension was sought and when I was fully satisfied, it was granted. I was particularly referring to question No. 16 and since the Leader of the Opposition has also just arrived, I will repeat it again. Question No. 16 was sent by this Secretariat to the Government on the 9th July, 1968, as per programme. The Secretary concerned issued a circular letter to other Departments asking for information ertaining to that question, on the 17th July, 1968, thus eight days had been wasted. That is what I am stressing upon the Government.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आयंदा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : शुक्रिया।

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Spekaer : Call Attention Notice No. 8, given by Shri Mangal Sein concerning Shir Karnail Singh, S.H.O., Police Station Rania, Tehsil Sirsa, District Hissar, is disallowed on the ground that is is a complaint against the

counduct of an individual employee. IN case the facts are correct, the official can be prosecuted in a Court of Law. Moreover, according to the Rules of Procedure and Conduct of Business, no business other that asking of questions can be transacted on the day of the presentation of the Budget.

May I now request the hon. Finance Minister to present the Budget for the year 1968-69 (Thumping by the House when the Finance Minister rose to present the Budget).

Presentation of Budget for the year 1968-69

वित्त मंत्री (श्रीमती औम प्रभा जैन) : श्रीमान ! मै 1968–69 के लेखा अनुदान पेश करने के लिए खड़ी होती हूं।

सदन को पता ही है कि हरियाणा में 21 नवम्बर, 1967 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके परिणामस्वरू৺ वर्ष 1968–69 के लिये हरियाणा राज्य की अनुमानित आय और खर्चे का विवरण 8 मार्च, 1968 को संसद के दोनो सदनों में पेश किया गया जबकि वित्त वर्ष के 31 जुलाई, 1968 को समाप्त होने वाले पहले चार महीनों क लिये लेखा–अनुदान प्राप्त किया गया। अब हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हो चुके है और प्रतिनिधि सरकार ने 21 मई, 1968 को कार्यभार संभाल लिया है। नई सरकार के उद्देश्यों और नवीनतम अनुमानों को ध्यान में रखते हुए बजट सम्बन्धी स्थिति का भी जाजा़ लिया गया है। इसके अनुसार मै

आज वर्ष 1968–69 के संशोधित वित्त अनुमान पेश करने के लिये उपस्थित हुई है।

देश आर्थिक कठिनाई से गुजरा है, परन्तु रबी की काफी अच्छी फसल होने से आशा की किरण धीरे धीरे बढ़ रही है। देश में वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 के दौरान आने वाले दो लगातार सूखों से समूचे तौर पर देशभर में खेती की पैदावार में कमी आ गई और औद्योगिक क्षेत्र में मंदा बना रहा। जिन्सों की पैदावार में कमी के कारण परिवहन तथा अन्य सेवाओं की जरूरी मांग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इस अवधि के दौरान अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजों की कमी बनी रही। थोक कीमतों का अखिल भारतीय सूचक आंकड़ा (1952–53 को आधार मानकर) सितम्बर, 1966 में 187.5 से बड़कर अक्तूबर, 1967 में 221 हो गया। इसमें 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 1951 के बाद अब तक के किसी एक साल में कीमतों के अन्दर सब से अधिक बढ़ती है। उसी अवधि के दौरान देश भर में श्रमिकों का खपत कीमत सूचक आंकड़ा समूचे तौर पर (1949 का आधार मानकर) 13.6 प्रतिशत बढ़ा जबकि हरियाणा में (1951–51 को आधार मानकर) यह वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही।

वर्ष 1966–67 के कठिन समय में हरियाणा में खुराक की पैदाबार बढ़ान का भरसक यत्न किया गया। यह कुछ संतोष की बात है कि पैदावार 1965–66 में 19.84 लाख टन से बढ़कर 1966–67 में 25.75 लाख टन हो गई। इससे 30 प्रतिशत बढ़ती

का पता चलता हे। उसी अवधि के दौरान तिलहन की पैदावार भी 1965–66 में 84,000 टन से बढ़कर 1966–67 में 90,000 टन हो गई। चीनी का उत्पादन 7.17 टन से घटकर 5.10 लाख टन रह गया।

हरियाणा में वर्ष 1967–68 में काफी उन्नति हुई। अनाज की वास्तविक पैदावार 31 लाख टन के आरम्भिक अनुमानों से काफी अधिक रही। 1967–68 में अनाज की पैदावार में यह बढ़ती केवल अच्छे मौसम के कारण ही नही थी बल्कि अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के प्रचार ओर नलकूपों (ट्यूबवैलों) के सम्बन्ध में सरकार के जोरदार प्रयत्नां का भी फल था 1967–68 की अच्छी फसल के साथ कीमतों में भी सुधार हुआ है। यह देखकर संतोष होता है कि अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1968 तक थोक बिक्री कीमतों का सूचक आंकड़ा 221 से घटकर 200 रह गया। इससे पता लगता है कि देश में कीमतों के साधारण स्तर में 9.5 प्रतिशत की कमी हुई। (प्रशंसा)

सरकार की अनाज सम्बन्धी नीति का उद्देश्य न केवल कीमतों को स्थिर रखना है बल्कि किसानों को वाजिब कीमत द्वारा पैदाबार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही उपभोक्ता को बड़ी जरूरी राहत भी देनी है। किसानों को उचित कीमत दिलाने के लिये सरकार ने मंडियों से अनाज की खूब खरीद की है, और पिछले साल प्रापत किए गए 50,000 टन अनाज के मुकाबले में इतने पहले ही दो लाख टन से अधिक गेहूं प्राप्त

कर ली है। इस मौसम के अन्त मक 50,000 टन और गेहूं प्राप्त होने की आशा है। इसका कुछ हिस्सा राज्य विपणन संघ (स्टेट मार्किटिग फैडरेशन) के जरिये प्राप्त किया जाएगा। लगभग 40,000 टन अनाज प्रान्तीय सुरक्षित भंडार के साथ सरकार कमी के समय में अनाज की कीमतों को काबू में रख सकेंगी। आशा है कि खेती की पैदावार की कीमतों के स्थिर रहने से सामान्य कीमत सूचक आंकड़े को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इस तरह राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भी विकास के यत्नों का काफी असर पड़ने लगेगा। आगे का काम स्पष्ट एवं चुनौती देने वाला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे साहस एवं लग्न से पूरा कर लेगें।

वित्तीय स्थिति

मार्च, 1968 में संसद के सामने रखे गए वर्ष 1968–69 के अनुमानों के अनुसार आशा थी कि वर्ष 1967–68 के अन्त में 241 लाख रूप्ये का घाटा रहेगा। फिर भी, मार्च के प्रारम्भिक लेखे से पता लगता है कि वित्त–वर्ष 1967–68 के अन्त में 771 लाख रूपये का घाटा रहेगा। शुरू में बकाये की इस कमी के असली कारण की अभी छानबीन की जानी है। यह काम महालेखापाल से मददवार लेखे का ब्योरा मिलने पर ही हो सकता है। इस कमी के दो स्पष्ट कारण है। इसका पहला कारण यह है कि पिछले वित्त वर्ष क अन्त में राजय सरकार क पास 241 लाख रूपये की खाद का भंडार पड़ा था। इसकी बिक्री से वर्ष 1968–69 के दौरान धन वसूल किया जायगा। इसका दूसरा कारण यह है कि 1967–68 की

वार्षिक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता का बकाया (80 लाख रूपये) अभी भारत सरकार से वसूल किया जाना है। इन दो मद्दों को हिसाब में लेने के बाद वास्तविक घाटा कम होकर 450 लाख रूपये रह जाएगा।

संसद के सामने रखे गए वर्ष 1968–69 के बजट प्रस्तावों का जायज़ा लिया गया। अब संशोधित स्थिति इस प्रकार है :–

	संशोधित अनुमान 1967–68	**बजट अनुमार 1968–69**	**संशोंधित बजट अनुमान 1968–**69
	लाख रूपयां मे		
(i)प्रारम्भिक शेष – (क) लेखा पुस्तकों के अनुसार	–2,26	–2,41	–7,71

(ख) खजाना बिलों में लगा धन			
प्रतिभूतियां	4,75	4,75	4,75
(ii) राजस्व लेखा–			
प्राप्तियां	62,17	67,99	69,66
खर्च	57,39	66,35	71,70
बचत (+) घाटा (-)	+ 4,78	+1,64	–2,04
(iii) पूंजीगत खर्च (निवल)	9,04	3,79	1,38
(iv) सरकारी ऋण–			
लिया गया कर्जा	36,77	45,87	46,67
ऋण की अदायगियां	29,41	42,00	42,00
निवल	+7,36	+3,87	+4,67
(v) कर्जे और पेशगियां–			
पेशगियां	16,63	16,70	16,70
वसूलियां	6,05	7,16	7,16
निवल	–10,58	9,54	9,54

(vi) अन्तर्राज्य समंजन			
(vii) फुटकर निधि (निवल)	21		
(viii) अनिधिक ऋण (निवल)	+25	+35	+35
(ix) जमा और पेशगियां (निवल)	+7,35	+7,55	+7,55
(x) प्रेषण (निवल)	−6	−6	−6
(xi) अंतशेष	−2,41	−2,39	−8,16
(क) लेखा पुस्तकों के अनुसार			
(ख) खजाना बिलों में लगा धन			
प्रतिभूतियां	4,75	4,75	4,75

ऊपर लिखी हर एक मद्द की तफसील में न जाकर, मै वर्ष 1968−69 के बजट अनुमानों में मार्च, 1968 में संसद् के

सामने पेश किए जाने के बाद होने वाली मुख्य तबदीलियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।

राजस्व प्राप्तियों

मार्च के बजट में 67,99 लाख रूपये की अनुमानित प्राप्तियों की बजाए राजस्व प्राप्तियां 69,66 लाख रूपये होने की आशा है। इस प्रकार इसमें 1,67 लाख रूपयें की बढ़ोतरी होगी। विभिन्न मुद्दो के अधीन 3,68 लाख रूपए की बढ़ती हुई है। इसमें देसी शराब के ठेकों की नीलामी में अधिक बोलियों के कारण 3,26 लाख रूपये की वृद्धि तो राज्य आबकारी शुल्क के अधीन हुई है। सरकारी नलकूपों से पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में काश्तकारों से पहले वसूल किए जाने वाले बहाव दर की वजाए अब खपत हुई बिजली के प्रत्येक यूनिट पर 25 पैसे लिए जाएंगे। इससे 38 लाख रूपये की अधिक प्राप्तिया होने की आशा है। इंतकाल की फीस की दूर में बढ़ौतरी के कारणों से 2,01 लाख रूपये की कमी हुई है। मंदे की स्थिति तथा अन्य कारणों से बिक्री कर की वसूली में कमी (1,79 लाख रूपये) हुई है। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के विकास के लिये वर्ष 1967–68 के दौरान सम्पति कर पर लिए गए 50 प्रतिशत अधिभार को समाप्त करने से कमी (22 लाख रूपए) रह गई। वर्ष 1968–69 की राजस्व प्राप्तियों में 1,67 लाख रूपये की निवल बढ़ती निकलती है।

66,35 लाख रूपयें का अब अनुमानित राजस्व खर्च, बढ़कर 71,70 लाख रूपये हो जायेगा। इस प्रकार वर्ष 1968–69 के मूल बजट अनुमानों में 5,35 लाख रूपये की बढ़ती होगी। इस रकम में से 220 लाख रूपये जनवरी, 1968 में दिए गए अतिरिक्त महंगाई भत्ते और स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ने के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर खर्च हुए। जिला हिसार और करनाल में बन्दोबस्त कार्य शुरू करने का निर्णय किया गया है और इस प्रयोजन के लिये 36 लाख रूपये की रकम रखी गई हैं।

कुछेक पहल दिए जाने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये 2,75 लाख रूपये औरखर्च किये जारहे है। इनके लिये पहले काफी धन नही रखा गयाथा इस संबंध मे पहले मद्द गांवों की योजक मागों और सड़कों तथा भवनों की देखभाल की व्यवसाि करना है। इनके लिये 1,25 लाख रूप्ये की अतिरिक्त रकम जुटाई गई है। हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। और जनता की मांग है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए। इसलिए इस प्रयोजन क लिये बजट में रखी गई मौजूदा रकमों के इलावा 50 लाख रूप्ये की रकम विशेष तौर पर जुटाई गई है। अकाल तथा बाढग्रस्त क्षेत्रों के लिये मौजूदा रकम (30 लाख रूपये) काफी नही है। और आर्थिक तौर पर पिछड़े इन क्षेत्रों को सहायता देने के लिये अत्यावष्यक योजनाओं के शुरू करने के उद्देश्य से 80 लाख रूपये की अतिरिक्त रकम रखी गई है।

(प्रशंसा) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये मार्च, 1968 के अनुमानों में पहले रखी गई 18,60 लाख रूप्यें की रकम के इलावा ''ग्राम पुननिर्माण तथा हरिजन कल्याण निधि' में डालने के लिये 20 लाख रूपये की ओर रकम रखी गई है। (प्रशंसा)

पूंजीगत लागत का निवल खर्च 1968–69 के बजट अनुमानों में रखी गई मूल रकम से थोड़ा कम है। पूंजीगत खर्चे मे यह कमी इस बात के कारण है कि राज्य ने 241 लाख रूपये के रासायनिक खादों के अनुमानों में रखे गए पूंजीगत खर्च में उतनी ही कमी हो जाएगी।

''लिये गए सरकारी ऋण'' की मद्द के अधीन प्राप्तियों से 80 लाख रूपये की बढ़ती का पता चलता है। इस बढ़ती का कारण यह है कि 1967–68 की योजना के संबंध मं राज्य द्वारा दिखाई गई प्रगति के फलस्वरूप भारत सरकार से 80 लाख रूपयै कर्जा मिलने की आशा है।

वित्त आयोग –

चालू, वर्ष में, राजय के अन्दर चलाए जाने वाले प्रस्ताविक विकास कार्यक्रमों का ब्योरा प्रस्तुत करने से पहले, मै एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना चाहूंगी। इसका राज्य की भावी आर्थिक व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मै पांचवे वित्त आयोग के गठन का जिक्र करना चाहूंगी जिसके अध्यक्ष श्री महावीर त्यागी

है। इस आयोज से कहा गया है कि वह केन्द्रीय साधनों और विभिनन राज्यों को वर्ष 1969–70 के राजस्वों के सहायक अनुदानों की बांअ संबंधी अन्तरिम रिपोर्ट सितम्बर, 1968 मे ंपेष करें। वित्त आयोजग अपनी अन्तिम सिफरारिशें जुलाई, 1969 में पेश करेगा। ये सिफारिशें पहली अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाली पंचवर्षीय योजना की अवधि के संबंध में होगी। राज्य सरकार ने अपना केस अन्तरिम रिपोर्ट के प्रयोजन के लिये वित्त आयोग के सामने पहले ही पेश कर दिया है। आयौग की अन्तिम रिपोर्ट के लिये राज्य सरकार अपना ब्योरेवार केस तैयार कर ही है। राज्य सरकार सारे मामले पर पूरी तरह विचार कर रही है। और आशा है कि राज्य की आर्थिक कठिनाइयों और विशेषकर शिक्षा, उद्योग और जल –सप्लाई के क्षेत्र में पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आयोग ऐसी सिफारिशें करेगा जिनेस हरियाणा के लागों को काफी राहत मिलेगी।

विकास खर्च

योजना आयोग ने शुरू में हरियाणा क`लिये केवल 21. 53 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना बनाइ थी। चूंकि इस सीमा के अन्दर राज्य के विकास कार्यक्रमां को पूरा नही किया जा सकता था, इसलिय संसद मे ंपेष किए गए बजट मं वर्ष 1968–69 का योजना खर्च बढ़ाकर 23.43 करोड़ रूप्ये कर दिया गया। योजना खर्च मे यह बढ़ती इसलिये हो सकी कि केन्द्र द्वारा पहले निर्धारित की गई केन्दीय सहायता की मात्रा 13.19 करोड़ रूपये ही रखने

के बावजूद भी राजय ने वार्षिक योजना में अपना हिस्सा 7.63 करोड़ रूपये से बढ़कर 9.53 करोड़ रूपये कर दिया। इस सरकार ने यह भी महसूस किया है कि कुछेक प्राथमिक वाले क्षेत्रों में राज्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये यह खर्च भी काफी नही है। जैसा कि मैने पहले बताया है, स्कूलों का दर्जा बढ़ाने, ग्राम सड़कों के निर्माण और अकाल तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिय रखी गई रकम में काफी बढ़ोतरी करने का विचार है।

विकास के क्षेत्र में खेती बाड़ी की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा हैं खेती–बाड़ी से सम्बद्ध क्षेत्रों में धन लगाने के लिये 410 लाख रूप्ये की रकम रखी गई है। बहुमुखी परियोजनाओं, बड़ी तथा छोटी सिचाई, सेम रोक उपायों तथा जल निकास और बिजली वितरण पर 1285 लाख रूपये खर्च करने का विचार है। इस तरह ुलि योजना खर्च मेंसे 1695 लाख रूपये की रकम अर्थात कुल रकम का 72.8 प्रतिशत खेती और सिचाई तथा बिजली योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बकाया 648 लाख रूपये उद्योग, सड़कों तथा सड़क–परिवहन और समाज सेवओं आदि के कई दूसरे क्षेत्रों में लगाने का विचार है।

खेती और सम्बद्ध कार्यक्रम

कृषि के क्षेत्र में सघन खेती और सिचाई के साधन अपनाने से क्राांति आ रही है। अच्छी खाद तथा खेती के बढ़िया

औजरों के अधिक से अधिक इस्तेमाल से खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जोरदार कोशिश की जा रही है। इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले वास्तविक कार्यक्रम काफी बड़ा है। खेती वर्ग के विषयों के लिय वार्षिक योजना में रखे गए 410 लाख टन रूपये के इलावा 8 करोड़ रूपये की अतिरिक्त रकम कृषि वित्त निगम, कृषि–पुनर्वित निगम और राज्य भूमि बन्धक बैंक तथा दूसरें सहकारी बैकों आदि की संस्थाओं के साधन से मिल सकेगी। इन संस्थाओं के जरिये प्राप्त किए गए धन को ज्यादातर लघु सिचाई सुविधाएं बढ़ाने क लिय प्रयोग किया जाएगा। खेती के क्षेत्र की दूसरी उधार संबंधी जरूरतों को सहकारी समितियों द्वारा पूरा किया जाएगा और आशा है कि लगभग 13 करोड़ रूपये तक का उधार सहाकरी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। इसक इलावा रासायनिक खादों के लिये तकावी कर्जा के रूप में 3 करोड़ रूपये दिए जाएंगे।

कृषि क्षेत्र के 410 लाख रूपये में से खेती की पैदावार संबंधी वार्षिक योजना में 138.46 लाख रूपये रखे गए है। और कृषि विष्वविद्यालय के लिये 30 लाख रूपये की और रकम रखी गई। पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम में जिला करनाल के सघन विकास कार्यक्रम के लिये 29.09 लाख रूपये, 25,000 एकड़ रकबे में कपास पर हवाई जहाज द्वारा दवाई छिड़कने के लिये 15.80 लाख रूपये और नकदी फसलों के प्रचार से सम्बन्धित स्कीमों के लिये 12.16 लाख रूपये शामिल है। अधिक पैदावार देने वाली

विभिन्न फसलों के अधीन लाएग गए 3.30 लाख एकड़ के मुकाबिले में, इस कार्यक्रम के अधीन 8 लाख एकड़ भूमि को लाया जाएगा। रासायनिक खाद का प्रयोग 1967–68 में 1.87 लाख टन था। अब 1968–69 मे इसके 3.15 लाख टन तक बढ़ जाने की आशा है।

वार्षिक योजना में लघु सिंचाई क्षेत्र के लिये 104 लाख रूपये की रकम रखी गई है। इसमें से राज्य के विभिन्न इलाकों में सरकारी नलकूप लगाने के लये 34.89 लाख रूप्ये रखे गए है। और निरन्तर सूखा ग्रस्त क्षेत्रां में लघु सिचाई कर्जे देने के लये 13 लाख रूपये की रकम रखी गई है। फिर भी, लघु सिंचाई के लिये अधिक धन संस्थागत सांधनों से जुटाया जाएगा। वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित निगम से लघु सिचाई कर्जो के रूप में कुल 4.56 करोड़ रूपये की रकम मिलने की सम्भावना है। इस राशि से 41,00 नलकूप/कुंए और 600 पम्पिग सेट लगाने का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके इलावा भूं–बंधक बैक से लघु सिंचाई कर्ज़ो के लिये 52 लाख रूपये की रकम जुटाई जा सकेगी। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि नए बनाये गए कृषि वित्त निगम ने सिद्धान्त रू॰ से अम्बाला जिला की नारायणगढ़ तहसील में लगभग 2 करोड़ रूपये की लागत से 200 गहरे नलकूप लगाने की स्की की मंजूरी दे दी है। आशा है कि इस स्कीम को लागू करने से जिला अम्बाला की नारायणगढ़

तहसील में खेाती बाड़ी की पैदावार बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

सहकारी क्षेत्र

मैने पहले ही बताया है कि किसानों को कर्जे देने मं सहकारी समितियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सहकारी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत हैं और इस प्रकार निकम्मी समितियों को समाप्त करने और न चल सकने वाली तथा छोटी समितियों का आपस में मिलाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। कृषि सम्बन्धी विभिन्न वस्तुओं, खासकर रसायनिक खादों को हरियाणा सहाकरी विपणन संघ और इससे सम्बद्ध संस्थाओं के माध्यम से बांटा जाएगा। वष्र 1967–68 में हरियाणा सहकारी विपणन संघ को हिस्सा पूंजी के रूप में 35 लाख रूपये दिए गए थे। संघ की हिस्सा पूंजी को और बढ़ानें का विचार है।

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

खेती सम्बन्धी कार्यक्रम के बारमें मे पशु पालन डेरी उद्योग के विकास को विशेश महत्व दिया गया है और इस प्रयोजन के लिये वार्षिक योजना में 44.87 लाख रूपये की रकम रखी गई है। राज्य को हरियाणा गाय और मुर्राह भैंसों की प्रसिद्ध नस्ल का घर होने का गर्व प्राप्त है। पशु विकास के महत्व की चर्चा करने की आवश्कता नही है। भारत सरकार द्वारा दिल्ली के चारों तरफ क्षेत्रों में दो व्यापक पशु विकास खंडों की स्थापना के

लिये एक विशेश योजना मंजूर की गई है। युगोस्लाविया से लिये सामान तथा मशीनों के कर्ज़े की सहायता के साथ 60 लाख रूपये की कुल लागत से जीन्द में क्रीम निकालने का एक देहाती कारखाना स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना पिछले वर्ष आरम्भ की गई थी और चालू वर्ष के दौरान इसके लिय 15 लाख रूपये की रकम रखी गई। आशा है कि इसका मिल्क प्लांट 1969 के मध्य में चालू हो जाएगा।

सिचाई तथा बिजली

सिंचाई, बिजली, बाढ की रोकथाम तथा जल निकास के लिये रखी गई कुल 1,285 लाख रूपये की रकम में से 740 लाख रूपये बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिये नियम कर दिए गए है। इसमें से 521 लाख रूपये ब्यास परियोजना के पहिले और दूसरों यूनिटों पर, 212 लाख रूपये भाखड़ा के दाहिने किनारे के बिजली संयंत्र पर तथा 7 लाख रूपये नई स्कीमों की छानबीन पर खर्च किए जाएंगे। वार्षिक योजना में थर्मल बिजली पैदा करने तथा पारेषण क लिये 3.5 करोड़ रूपये की रकम रखी गई। सिंचाई सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये बड़ी तथा दरमियानी सिंचाई योजनाओं के लिये 113 लाख रूपये की रकम रखी गई है। इसमें गुड़गांव नहर परियोजना, पश्यिमी यमुना नहर को नया रूप देना तथा फीडर परियोजनाएं, रिवाड़ी उठाना योजना तथा दादरी सिंर्चा शामिल है। इस कुल खर्चे से, पश्चिमी यमुना के इलाके में नलकूप बनाने के लिये भी 17.45 लाख रूपये

की रकम रखी गई है। बाढ़ की रोकथाम, सेम–रोक उपायों तथा जल निकास योजनाओं क लिये 82.50 लाख रूपये रखे गए है। इसमें से 77 लाख रूपये मौजूद योजनाओं पर तथा 5.50 लाख रूपये नई योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।

मै हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की गई प्रगति का भी जिक्र करना चाहूंगी जिसने 2 मई, 1968 को अपना पहला वर्ष पूरा किया। यह बात जिक्र के काबिल है कि राज्य में पिछले 17 वर्षो में बिजली दिए गए 20,000 नलकूपां के मुकाबिले में वर्ष 1967–68 में, 7,359 नलकूपों को बिजली दी गई। दो और पारेषण लाइनें अर्थात धूलकोट शाहबाद–पिपली तथा पानीपत–सोनीपत लाइनें पिछले साल के दौरान मुकम्मल हुई। 6 उप–स्टेशनों, अर्थात शाहबाद, पिपली, हिसार, सोनीपत, जगाधारी तथा करनाल का भी विस्तार किया गया है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि बोर्ड ने तकनीकी संभवता की शते के साथ उपभोक्ताओं के कई वर्गो पर लगाई गई पाबन्दियां हटा दी है।

चालू वर्ष के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के बजट में 13.15 करोड़ रूपये की रकम रखी गई है। इसका इस्तेमाल 132 के.वी. तथा इससे कम की लाइनें लगाने, वितरण प्रणाली फैलाने तथा बढ़ाने और खेती सम्बन्धी एंव औद्योगिक कनैक्शनद ने के लिये किया जाएगा। चालू वर्ष में 15,000 नलकूपों को बिजली देने का निशाना रखा गया है। जबकि पिछले वर्ष 7,359 नलकूपों को बिजली दी गई थी। बोर्ड ने 1,600 औद्योगिक

कनैक्शनों ओर 40,000 साधारण सेवा कनैक्शनों का भी निशाना रखा है। 2,000 से अधिक आबादी वाले 200 गांवों को भी बिजली देने का विचार है। 220 के.वी. हिसार, बल्लभगढ़ लाइन परम आवश्यक पारेषक परियजाओं में से एक है। इसे पहले ही मंजूर किया जा चुका है और राज्य के आर्थिक विकास में इसका विशेष महत्व होगा।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग

हरिजन कल्याण के लिये सरकारी सहायता एवं विकास निगम स्थापित किया गया है जो माल तैयार करके बेचने मं लगे हरिजनोंकी सहाकारी समितियो को वित्तीय तथा प्रबन्धकीय सहायता देगा। चालू साल की योजना में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये 25 लाख रूपये रखे गए है। इनमें से 14.95 लाख रूपये हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे तथा फीस की रियातेह देने पर खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने के लिये 45 रूपयेकी मासिक दर से वजीफे दिए जाते हैं ग्राम पुननिर्माण तथा हरिजन कल्याण निधि के लिये 18.60 लाख रूपये की रकम पहले ही दइ गई थी। वर्तमान सरकार ने इस वगों को अधिक से अधिक सुधार करने का दृढ़ निश्चय किया है। इसलिए हरिजन कल्याण निधि में 20 लाख रूप्ए की अतिरिक्त राशि डालने का निर्णय किया गया है।(प्रशंसा)

उद्योग

आदरणीय सदस्यों को यह तो भलीं भांति विदित है। कि राज्य में विशेषकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास की काफभ सम्भावाना है। वार्षिक योजना में इसके लिए 97 लाख रूपये खर्च करने का विचार ह। इसमं से 30 लाख रूपये कर्जा सुविधाओं के रूप में लघु–उद्योगों के लिये 13.15 लाख रूपये, गैर सरकारी उद्योगों में पूंजी की गारंटी देने के लिये और 7.55 लाख रूपये उकलाना में सहकारी कताई मिल लगाने के लिये रखे गए है। प्रमुख उद्योग केन्द्रों के विकास के लिये एक योजना बनाई गई है। गैर सरकारी कारखानेदारों को नए औद्यागिक यूनिट लगाने के लिये आर्थिक सहायता की पेशकश और अन्य सुविधाओं द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महेन्द्रगढ़ एवं गुड़गांव में खनिज पदार्थो के मिलने की सम्भावना हैं इनके उपयोग के लिये 3.50 लाख रूपये खर्च करने का विचार है।

तकनीकी शिक्षा के लिये 40 लाख रूपये तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये 12 लाख रूपये रखे गए हैं रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र को 11.50 लाख रूपये क सहायता अनुदान के इलावा वाई०एम०सी०ए० संस्थान, फरीदाबाद के लिये 9 लाख रूपये की रकम रखी गई है जर्मन नमूने पर बनी इस संस्था द्वारा मध्यम स्तर के तकनीकी माहिरों को विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में धन्धों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंजीनियरी

कालेजों में पड़ रहे निर्धन एवं सुपात्र विद्यार्थियों को 6.50 लाख रूपये दिए जाएंगे।

चाहे योजना खर्च की लगभग 73 प्रतिशत राशि खेती, सिंचाई और बिजली के लिये रखी गई है, फिर भी शिक्षा के लिये काफी धन जुटाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में पड़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम हैं हरियाणा में केवल 19 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे है। जबकि इसके मुकाबिले में पंजाब के अन्दर 29 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे है। वर्ष 1967–68 के दौरान शिक्षा के लिये रखी गई 144.50 लाख रूपये की रकम के मुकाबिले में चालू वर्ष की वार्षिक योजना के लिये यह खर्च बढ़ा कर 9.3 प्रतिशत कर दिया गया है। फिर भी शिक्षा की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये यह बढ़ाई के लिये चालू वर्ष के बजट में 50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि रखी गई है। आशा है कि बढ़ाई गई रकम से वर्ष 1968–69 के दौरान एक लाख और बच्चों को स्कूलों में अतिरिक्त दाखिला दिया जा सकेगा।

चिकित्सा और स्वास्थ्य

गत वर्श की भांति परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सब से अधिक पहल दी जा रही है और इस उद्देश्य के लिये 75.79 लाख रूपये की कुल रकम रखी गई है। 23.77 लाख रूपये की रकम चिकित्सा के लिये रखी गई है। जिला अस्पताल और 12 तहसील अस्पतालों कासुधार किया जाएगा। पहले सहे ही चल रहें

15 आयुर्वेदिक औषधालयों को चलाने के इलावा सियोल में 10 बिस्तरों वाल एक और आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त उद्योग कामगरों को भी इलाज की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन 50 बिस्तरें वाले एक अस्पताल के मुकम्मल हो जाने की आशा है। उद्योग कामगरों और उनके परिवारों को अस्पताल के अन्दर और वाहर इलाज के लिये अधिक सुविधाएं देने के वास्ते कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन 24 लाख रूपये की रकम रखी गई है।

राज्य में पीने के पानी की सप्लाई की समस्या बडद्यी गम्भीर है और अधिकतकर गांवों में जल सप्लाई संतोषजनक प्रबन्ध नही है। बहुत से स्थानों पर जमीन के पानी का तल बहुत नीचा है औश्र प्रायः पानी खारा है देहाती और शहरी इलाकों में जल सप्लाई के प्रबन्ध को ठीक करने की विशेश यत्न किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये चालू साल में कुल 38 लाख रूपये रखे गए है। वर्तमान सरकार इस रकम को काफी नही समझती। इसलिये अकाल सहायता के अधीन 80 लाख रूपये की अतिरिक्त रकम का अधिकतर हिस्सा कमी वाले इलाकों में पानी का प्रबन्ध करने के लिये नियत करेगी। (प्रशंसा)

सड़कें

रेल सुविधाओं की कमी के कारण हरियाणा में सड़कों के विकास का विशेष महत्व है और इस उद्देश्य के लिये वार्षिक योजना मे एक करोड़ रूपये की रकम रखी गई है। इस कार्यक्रम मे अम्बाला जगाधरी–शाहजहानपुर सड़क पर एक ही और बेगना, अमरी, टांगरी और सुखना नदियों पर ऊंचे पुल बनवाने का विचार हैं गांवों से जोड़ने वाली सड़कों और पहंचम मार्गो पर ज्यादा जोर दिया गया है। 21.05 लाख रूपये की पहले रखी गई रकम के इलावा 125 लाख रूपये की अतिरिक्त रकम भी जुटाई गई है। (प्रशंसा)

सरकारी कर्मचारियों की रियातें

बढ़ती हुई कीमतों के कारण सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों से सरकार भली भांति परिचित है। वित्तीय कठिनाइयों के होते हुए भी सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंमाई भत्ते के रूप में काफी राहत दी है। इस बात पर जोर दिया जा सकताहै कि हरियाणा उन कुछ पहले राज्यों मेंसे है, जिन्होने अपनी कर्मचारियों को केन्दीय दर पर महंगाई भत्ता देकर पूरी रहात पहुंचाई है। इस प्रकार राज्य सरकार ने पहली दिसम्बर, 1967 से कीमत सूचक आंकड़ें में 20 की बढ़ोतरी के लिये अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया है। उपभोक्ता कीमत सूचक आंकडे के 195 से 205 तक बढ़ने के फलस्वरू पहली जनवरी, 1963 से महंगाई भत्तों में और भी बढ़ोतरी की गई है। इन अतिरिक्त महांगई भत्तों और पहली

जून, 1967 को दिये गए पहले महंगाई भत्ते के संबंध में राज्य के खजाने पर हर वर्ष कुल 4.30 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा।

केन्दीय सरकार की दर पम महंगाई भत्ता दिए जाने के अतिरिक्त विश्व–विद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली नवम्बर, 1966 से कालेज अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाए गए है। पहली दिसम्बर, 1967 से कोठारी आयोग की सिफारिशों को ध्यान मं रखते हुए स्कूल अध्यापकां के वेतन मान बढ़ा दिए गए है। वेतन मानों के कारण हर वर्ष 1.50 करोड़ रूपये का खर्च उठने का अनुमान है।

सरकारी पेंशन लेने वाले तथा उनके परिवारों के लिये सरकार द्वारा कुछ रियायतों की भी घोषणा की गई है। हरियाणा राज्य के पेंशन लेने वालों का अब राज्य क अस्पतालों और औषधालयों में एक्स रे, प्रयोगशाला और अन्य चिकित्सा सुविधाओं समेंत अस्पताल के अन्दर और बहिर इलाज की ऐसी सुवधिा मिलेगी जैसी कि उन्हें नौकरी से हटने के समय थी। मुक्त इलाज में ऐसी दवाईयों को सप्लाई भी शामिल है जो राज्य के अस्पतालों और औषधालयों में मिल सकती है।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई राहतऔर अपने पेंशन–भोगियों की कठिनाइयों कम करने के लिय `किए गए विभिन्न उपायों की सराहना करेगे। कठिन वित्तीय स्थिति के कारण ऐसा करने से

सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ेगा। आशा है कि सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह जागरूक रहेंगे और राज्य की भलाई के लिये अपना पूरा प्रयत्न करेंगे।

कर ढांचे को सरल बनाना

अब मै वर्तमान करों के वर्तमान ढांचे को सरल बनाने के प्रश्न की चर्चा करूंगी। ऐतिहासिक कारणों से राज्य में बिक्री कर का ढांचा ऐसे ढंग से बना हुआ था किस सराफा माल 1/2 प्रतिशत से लेकर विलास की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तक बहुत से दर प्रचलित थे। इस समय विभिन्न वस्तुओं पर करों की आठ विभिन्न दरें लागू है। करों के ऐसे ढाचें को सरल बनाने के लिये सरकार ने कई चीजों पर लगाने वाले करों की दरों की संख्या 8 से घटाकर 6 कर दी है।

वर्तमान करों से अधिक से अधिक लाभ उठाने के उठाने के उद्देश्य से सरकार ने करों के आंकने, वसूल करने तथा अपराधियों के पकड़ने में सरकारी तन्त्र की कुशलता को बढ़ाने के उपाय किए है। निरीक्षण निदेशालय की स्थापना से लागू करने और निरीक्षण के प्रबन्ध भी मजबूत बनाए गए है।

माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जो सुझाव देना चाहें, उनका स्वागत किया जाएगा और उन पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा।

साधन–संग्रह

अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्तावों की चर्चा से पहले, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य सरकान ने संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति के होते हुए भी, पहली अगस्त, 1968 से राज्य क सभी सरकारी स्कूलों मैं बच्चों के लिये आठवी कक्षा तक मुक्त शिक्षा फिर से लागू करने का निश्चय किया है। (प्रशंसा)

माननीय सदस्यों को पता ही है। कि हरियाणा में बहुत कम लोग पढ़े लिखे है और नई सरकार ने राज्य के सभी निवासियों को शिक्षा का समान अवसर देने का निश्चय किया है। निःसन्देह इससे राज्य की आय में 82 लाख रूपये का घाटा पड़ेगा। यह घाटा निश्चय ही समाज के व्यापक हित में है और मुझे विश्वास है कि सभी दलों के माननीय सदस्य घोषित किए गए उपायों का स्वागत करेंगे।

यद्यपि कोई मुख्य कर लगाने का सुझाव नही है, फिर भी अधिक घाटे का ध्यान म ंरखते हुए, सरकार ने कुरूक्षेत्र के विकास के लिये भू–राजस्व तथा सम्पति कर पर 50 प्रतिशत अधिभार एक वर्ष क जारी रखने का फैसला लिया है। इस साधन से 50 लाख रूपये की आमदनी होगी। इस धन को कुरूक्षेत्र नगर तथा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के विाकस के लिये प्रयोग किया जाएगा। राज्य सरकार कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय बनाना चाहती है। कुरूक्षेत्र में हमारी प्राचीन वैदिक सम्भयता पनपी है तथा यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक संस्थाओं के कारण हरियाणा निवासियों के लिये अधिक महत्व का

स्थान है। हरियाणा सरकार कुरूक्षेत्र नगर का भी विकास करना पसंद करेगी ताकि यह नगर अपने प्राचीन गौरव को फिर से प्राप्त कर सके और देश के वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण स्थान ले सकें।

भू–राजस्व तथा सम्पति करक अधिभार को चालू रखने के अतिरिक्त हरियाणा में सरकारी लाटरी शुरू करने का विचार है। केरल में इसके प्रयोग ने सिद्ध कर दिया है कि यह आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन है। यदि इसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय तो इससे खजाने को काफी धन मिल सकेगा। लाटरी के स्वैच्छिक होने के कारण इस योजना में विवशता का कोई अंष नही है। इस योजना से पूरे वर्ष 40 लाख रूपये की आमदनी होने की सम्भावना है वर्ष के तीन मास पूरे हो चुकने के कारण राज्य सरकार को लगीाग 25 लाख रूपये की आमदनी होने की सम्भावना है।

इन उपायों से सरकारी खाजने को 75 लाख रूपये की अतिरिक्त आमदनी होने की आशा है आठवी कक्षा तक फिर से मुफ्त शिक्षा आरम्भ करने के कारण बजट में 82 लाख रूपये का घाटा पड़ेगा। इससे राज्य का कुल घाटा 7 लाख रूपये बढ़ जाएगा और अब यह घाटा 823 लाख रूपये हो जाएगा। मै इस घाटे के बजट को फिलहाल इसी तरह रहने देती हूं क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने कोई ऐसा नया कर लगाने क निर्णय नही किया है जिससे जनसाधारण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रू‍प से कोई बुरा प्रभाव पड़े। (प्रशंसा)

राज्य सरकार का प्रयत्नइ स घाटे का मुख्य कारण यह भी है कि चालू वर्ष में भाखड़ा नंगल परियोजना के कर्जो की अदयगी के लिये 10.30 करोड़ रूपये की राशि रखी जानी थी। अदायगीकी इस बहुत बड़ी रकम ने किसी अन्य आत की अपेक्षा कही अधिक हमारे बजट पर बुरा प्रीााव डाला है। हम केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालते रहे है ताकि वह कर्जे को पुनः नियत करें, तथा हमें आशा है कि चालू वर्ष के दौरान कुछ राहत मिल जाएगी।

राज्य में विकास की पर्याप्त संभावनाएं है। अपने भाषण के दौरान मुझे अनाज की पैदावार में आशाजनक विकास का जिक्र करने का मौका मिला। इस महत्वपूर्ण आर्थिकक्षेत्र में यह सफलता राज्य के लिए शुभ लक्षण है। आशा है कि राज्य के साधनों के इलावा, कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिये धन गैर सरकारी बचतों तथा अन्य संस्थाओं के साधनों से बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा।

अभी तक उपेक्षित तथा पिछड़े हुए इस राज्य का विकास एक महान कार्य है तथा मुझे आशा है ि कइस सदन के माननीय सदस्य हमारी आर्थिक अवस्था के तेज विकास के लिय उचित वातावरस बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग देंगे।

आभार प्रदर्शन

मै योजना तथा वित्त कमिश्नर और वित्त विभाग के अन्य अधिकारियायें तथा कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझती हूं उन्होने थोडे से समय में बजट का जायजा तैयार करने में इतना परिश्रम किया है। मै महालेखपाल, हरियाणा तथा संघीय क्षेत्र, चंडीगढ़ के प्राधिकारियों की भी आभारी हूं कि उन्होने समय पर सहयोग दिया है।

श्रीमन, अब मै आपकी इजाजत से वर्ष 1968–69 के संशोधित बजट अनुमान पेश करती हूं। (प्रशंसा)

जय हिन्द

(The Sabha then adjorned till 2-00 P.M. on Monday, the 22nd July, 1968)